

DAILY CURRENT AFFAIRS

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 01-10-25



The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Wednesday, 01 Oct, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 04 Syllabus : GS 3 : Environment / Prelims	भारत में इस साल 8 फीसदी ज्यादा मॉनसून बारिश हुई: IMD
Page 06 Syllabus : GS 2 : Governance / Prelims	2023 में सड़क दुर्घटनाओं में 1.73 लाख से अधिक लोगों की मौत, 1.6% की वृद्धि: NCRB
Page 06 Syllabus : GS 1 & 2 : Social Issues and Governance / Prelims	महाराष्ट्र, कर्नाटक में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की
Page 09 Syllabus : GS 2 & 3 : Social Justice and Indian Economy/ Prelims	अधिक महिलाएं श्रम बल में शामिल होती हैं, लेकिन क्या वे वास्तव में कार्यरत हैं?
Page 12 Syllabus : GS 3 : Indian Economy / Prelims	FPI लगातार तीसरे महीने भारतीय शेयर बाजारों से बाहर
Page 09 : Editorial Analysis Syllabus : GS 1 & 2 : Social Issues and Governance	लड़कियों की शिक्षा का परिवर्तन

दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून-सितंबर) भारत की कृषि अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, जो वार्षिक वर्षा में लगभग 75% का योगदान देता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, 2025 में, भारत में सामान्य से 8% अधिक मानसून वर्षा हुई, जो 2001 के बाद से 5वीं सबसे अधिक और 1901 के बाद से 38वीं सबसे अधिक बारिश है।

India got 8% more monsoon rainfall this year, says IMD

Jacob Koshy
NEW DELHI

India this year received 8% more monsoon rainfall than normal, the fifth-highest since 2001 and the 38th highest since 1901, the India Meteorological Department (IMD) said on Tuesday.

The IMD considers only the rainfall from June 1 to September 30 to calculate monsoon data.

While the southwest monsoon season largely boded well for agriculture by boosting storage in reservoirs, it wreaked havoc in several parts of the country – particularly in North India – leading to

loss of life and property.

Seasonal rainfall over northwest India, central India, and south peninsula was 27%, 15% and 10% more than their seasonal averages. However, rainfall in eastern and northeastern India was 80% of what those regions usually get.

The rainfall over north-west India was 74.79 cm, the highest since 2001 and sixth highest since 1901, while that over east and northeast India was 108.9 cm, the second lowest since 1901. Overall, the monsoon rainfall was 93.7 cm.

The monsoon season saw extremely heavy spells in several parts of northern

Pouring patterns

Monsoon rains were uneven across India, with reservoirs filling in some regions while others faced a dry spell

■ Northwest sees record rainfall of 27% above seasonal average, the highest since 2001

■ Central India and south peninsula see above-average rainfall 15% and 10% higher than their seasonal averages

■ East and Northeast face deficit, receiving only 80% of usual rainfall, the second-lowest since 1901



and southern India, thanks to the conjoining of storms that originated in the Mediterranean region, along with the monsoon trough that hovers over the Indian landmass during the monsoon season. When parsed

by months, rainfall was 9% more than what is usual in June, 5% more in both July and August, and 15% excess in September.

The southwest monsoon advanced over the south Andaman Sea and

Nicobar Islands on May 13, 2025, nearly nine days ahead of the normal schedule. It arrived in Kerala on May 24, ahead of the usual onset date of June 1, and covered the entire country by June 29.

There were seven monsoon depressions, or sub-cyclonic storms that form in the Arabian Sea and the Bay of Bengal, during the season. Of the seven, one intensified into a deep depression. Storms falling in this category last an average of 69 days against a normal of 55, contributing to the extended spells of heavy rain.

Though the monsoon system has not fully with-

drawn and will prevail over the next couple of weeks, the IMD does not count that rain in its quota of monsoon rainfall. For October, the agency has forecast 'above normal' rain in the country, except for parts of north and north-west India.

While a La Nina is expected to form in the central equatorial Pacific Ocean and it usually means a stronger winter, IMD Director-General M. Mohapatra said this was not always the case.

A forecast for winter (December, January and February) will be available around November, he added.

वर्तमान संदर्भ

- **समग्र मानसून (2025):**
 - कुल वर्षा: 93.7 सेमी (सामान्य से 8% अधिक)।
 - समयरेखा: जल्दी (केरल में 24 मई, सामान्य 1 जून) और 29 जून तक पूरे भारत को कवर किया गया।
- **क्षेत्रीय वितरण:**
 - उत्तर पश्चिम भारत: +27% (2001 के बाद से सबसे अधिक, 1901 के बाद से छठा सबसे ऊंचा; 74.79 सेमी)।
 - मध्य भारत: +15%।
 - दक्षिण प्रायद्वीप: +10%।
 - पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत: घाटा (सामान्य का 80 प्रतिशत, 1901 के बाद से दूसरा सबसे कम; 108.9 सेमी)।
- **मासिक वर्षा:**
 - जून: +9%
 - जुलाई: +5%
 - अगस्त: +5%
 - सितंबर: +15%
- **तूफान/अवसाद:**
 - 7 मानसून अवसाद (अरब सागर + बंगाल की खाड़ी), 1 गहरा दबाव का क्षेत्र।
 - 69 दिनों बनाम सामान्य 55 दिनों तक चला, जिससे भारी बारिश हुई।
- **प्रभाव:**
 - सकारात्मक: कृषि सहायता → उच्च जलाशय भंडारण।

- नकारात्मक: उत्तर और दक्षिण भारत में बाढ़, भूस्खलन, जान-माल की हानि।

स्थैतिक संदर्भ

1. मानसून तंत्र:

- भूमि और समुद्र के अंतर तापन + अंतर-उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र (आईटीसीजेड) + सोमाली जेट + मानसून गर्त द्वारा संचालित।
- आमतौर पर 1 जून (केरल) से शुरुआत होती है। राजस्थान से सितंबर-अक्टूबर में नाम वापस लेना शुरू होगा।

2. संबद्ध जलवायु कारक:

- ला नीना (प्रशांत में ठंडा): आमतौर पर मानसून/बारिश को मजबूत करता है।
- अल नीनो (वार्मिंग): आमतौर पर भारतीय मानसून को कमजोर करता है।
- हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD): सकारात्मक चरण वर्षा को बढ़ाता है।

3. भारत के लिये महत्व:

- ~ 50% कार्यबल मानसून संचालित कृषि पर निर्भर है।
- सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि, खाद्य मुद्रास्फीति, पनबिजली और जल सुरक्षा को प्रभावित करता है।

प्रभाव

1. आर्थिक:

- अच्छी वर्षा → बेहतर खरीफ उत्पादन (चावल, दालें, मोटे अनाज)
- जलाशयों और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा मिलेगा जिससे रबी फसलों को सहायता मिलेगी।
- जलविद्युत उत्पादन का समर्थन करता है।

2. सामाजिक और पर्यावरण:

- उत्तर भारत में बाढ़ शहरी नियोजन और नदी बेसिन प्रबंधन की संवेदनशीलता को दर्शाती है।
- पूर्वोत्तर भारत में कमी चाय उत्पादन, स्थानांतरण खेती और जैव विविधता पर चिंता पैदा करती है।

3. रणनीतिक और जलवायु:

- शुरुआती शुरुआत और विस्तारित अवसाद जलवायु परिवर्तन के तहत मानसून के बदलते पैटर्न का संकेत देते हैं।
- आपदा तैयारियों, जलवायु-अनुकूल कृषि और पूर्व चेतावनी प्रणालियों के लिए नीतिगत मांग बढ़ाई।

निष्कर्ष

2025 के मानसून ने राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य से अधिक वर्षा की, जिससे कृषि और जल भंडारण को बढ़ावा मिला, लेकिन भारत की बाढ़-भेद्यता और क्षेत्रीय असंतुलन को उजागर किया गया। मानसून को प्रभावित करने वाली जलवायु परिवर्तनशीलता (ला नीना, आईओडी, ग्लोबल वार्मिंग) के साथ, भारत को जलवायु-अनुकूल खेती, बाढ़ प्रबंधन और जल विज्ञान योजना को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। खाद्य सुरक्षा और आपदा तैयारी दोनों सुनिश्चित करते हुए वर्षा की प्रचुरता को लचीलेपन में बदलने की चुनौती है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा अल नीनो और ला नीना के बीच अंतर का सही वर्णन करता है?

- (a) अल नीनो प्रशांत महासागर के जल का गर्म होना है, जबकि ला नीना असामान्य रूप से शीतलन है।
- (b) अल नीनो भारतीय मानसून को मजबूत करता है, जबकि ला नीना इसे कमजोर करता है।
- (c) अल नीनो और ला नीना दोनों ही भारत में समान जलवायु प्रभाव डालते हैं।
- (d) अल नीनो और ला नीना ENSO (अल नीनो-दक्षिणी दोलन) चक्र से असंबंधित हैं।

उत्तर : a)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: बताएं कि ला नीना, भूमध्यसागरीय मूल के तूफान और मानसून अवसाद जैसी जलवायु घटनाएं भारत में वर्षा के स्थानिक और अस्थायी वितरण को कैसे प्रभावित करती हैं। **(250 शब्द)**

भारत दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं की दर सबसे अधिक वाले देशों में से एक है। 2023 के लिए नवीनतम एनसीआरबी (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो) के आंकड़े इस संकट की दृढ़ता पर प्रकाश डालते हैं: 4.64 लाख सड़क दुर्घटनाओं में 1.73 लाख से अधिक मौतें और 4.47 लाख घायल हुए। मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 और सड़क सुरक्षा अभियानों जैसे नीतिगत प्रयासों के बावजूद, 2022 की तुलना में मौतों में 1.6% की वृद्धि हुई है।

मुख्य निष्कर्ष (वर्तमान संदर्भ)

- कुल दुर्घटनाएं (2023): 4,64,029 (2022 से 17,261 अधिक)।
- मृत्यु: 1,73,826 मौतें (↑ 1.6 में 1,71,100 से 2022%)।
- चोटें: 4.47 लाख।

पीड़ित श्रेणियाँ:

- दोपहिया वाहन सवार: 79,533 मौतें (कुल मौतों का 45.8%)।
- पैदल यात्री: 27,586 (15.9%)।
- एसयूवी/कार/जीप: 24,776 (14.3%)।

राज्यवार रुझान:

- तमिलनाडु (11,490) और उत्तर प्रदेश (8,370) में सबसे अधिक दोपहिया वाहनों की मौत हुई है।
- उत्तर प्रदेश में SUV/कार से होने वाली मौतों में 19.2 फीसदी और ट्रक से संबंधित मौतों में 29.9 फीसदी मौतें हुईं।

दुर्घटनाओं का समय:

- 20.7% शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच हुआ।

घातक दुर्घटनाओं के कारण:

- तेज गति: 58.6% (1,01,841 मौतें)।
- खतरनाक/लापरवाही से गाड़ी चलाने और ओवरटेक करने की प्रवृत्ति: 23.6 प्रतिशत (41,035 मौतें)।
- अन्य कारण: शराब/ड्रग्स, खराब मौसम, जानवरों को पार करना (4,952 मौतें)।

सड़क श्रेणियाँ:

Over 1.73 lakh killed in road accidents in 2023, 1.6% rise: NCRB

Press Trust of India
NEW DELHI

More than 1.73 lakh people were killed and 4.47 lakh injured in road accidents across the country in 2023 with nearly 46% of the victims being two-wheeler riders, according to a report of the National Crime Records Bureau (NCRB).
Speeding and careless driving were found to be the two major causes of road accidents.

A total of 4,64,029 road accidents took place in the country in 2023, 17,261 more than in 2022 – with a 1.6% increase in fatalities, from 1,71,100 in 2022 to 1,73,826 in 2023.

The highest number of accidents (20.7% of total) were reported between 6 p.m. and 9 p.m.

Two-wheelers accounted for the highest number of fatal road accidents, causing 79,533 deaths, or 45.8% of total deaths, followed by pedestrians at 27,586 (15.9%) and SUV/car/jeep at 24,776 (14.3%).

Most of the deaths in two-wheeler accidents were reported in Tamil Nadu (11,490) and Uttar Pradesh (8,370). A large number of deaths due to SUV/car/jeep accidents were reported in Uttar Pradesh (19.2% of total) and a

Crash course

The NCRB report of 2023 has found that the reason for most fatal road accidents was speeding



■ 58.6% (1,01,841) of deaths attributed to speeding

■ 23.6% (41,035) of deaths attributed to dangerous driving or overtaking

■ Poor weather, driving under the influence and animal crossings caused 4,952 deaths

large number of deaths due to trucks/lorries/mini truck accidents were also reported in the State (29.9% of total).

The NCRB said cause-wise analysis of fatal road accidents revealed that 58.6% (1,01,841) and 23.6% (41,035) of fatalities were due to speeding and dangerous/careless driving or overtaking, respectively.

Poor weather conditions, driving under influence of drug/alcohol and animal crossing caused 4,952 deaths.

The highest number of deaths were reported on the National Highways accounting for 34.6%, followed by State Highways at 23.4%.

- राष्ट्रीय राजमार्ग: 34.6% मौतें।
- राज्य राजमार्ग: 23.4%।

स्थैतिक संदर्भ

- एनसीआरबी: गृह मंत्रालय के तहत, सालाना अपराध और दुर्घटना के आंकड़े एकत्र और प्रकाशित करता है।
- भारत में सड़क सुरक्षा:
 - मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019: सख्त दंड, मदद करने वालों के लिए सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन।
 - राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति (2010): सड़क सुरक्षा के लिए व्यापक ढांचा।
 - ब्रासीलिया घोषणा (2015): भारत 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है (संयुक्त राष्ट्र एसडीजी 3.6 के साथ संरेखित)।
 - सड़क सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई का दशक (2021-2030): सड़क यातायात से होने वाली मौतों और चोटों के 50% को रोकने के लिए वैश्विक लक्ष्य।

प्रभाव

1. आर्थिक:

- सड़क दुर्घटनाओं से भारत को सालाना सकल घरेलू उत्पाद का 3-5% खर्च होता है (विश्व बैंक का अनुमान)।
- उच्च स्वास्थ्य देखभाल बोझ और उत्पादकता हानि।

2. सामाजिक:

- यह युवाओं और कामकाजी आबादी को असमान रूप से प्रभावित करता है, जिससे जनसांख्यिकीय लाभांश कम हो जाता है।
- दोपहिया और पैदल चलने वालों की मौतें शहरी नियोजन और प्रवर्तन अंतराल को उजागर करती हैं।

3. शासन और नीति:

- कमजोर यातायात प्रवर्तन, लेन अनुशासन की कमी, अपर्याप्त सड़क इंजीनियरिंग।
- इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आईटीएस) और सड़क सुरक्षा ऑडिट को धीमी गति से अपनाना।

आगे की राह

1. इंजीनियरिंग समाधान: सुरक्षित सड़क डिजाइन, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, पैदल यात्री क्षेत्र, सख्त राजमार्ग ऑडिट।
2. प्रवर्तन: तेज गति, हेलमेट, सीट बेल्ट और नशे में गाड़ी चलाने पर सख्त कार्रवाई।
3. शिक्षा और जागरूकता: व्यवहार अभियान (जैसे *सड़क सुरक्षा अभियान*)।
4. आपातकालीन प्रतिक्रिया: तेज़ आघात देखभाल और दुर्घटना रिपोर्टिंग प्रणाली।
5. प्रौद्योगिकी: एआई-आधारित निगरानी, स्पीड कैमरे और जीपीएस-सक्षम प्रवर्तन का उपयोग।
6. संस्थागत तंत्र: राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद को मजबूत करना और राज्यों को धन और प्रौद्योगिकी के साथ सशक्त बनाना।

निष्कर्ष

2023 के लिए एनसीआरबी डेटा भारत के निरंतर सड़क सुरक्षा संकट को रेखांकित करता है, जहां तेज गति और लापरवाह ड्राइविंग प्रमुख हत्यारे बने हुए हैं। लगभग आधे पीड़ित दोपहिया वाहन सवार हैं, यह मुद्दा शहरी परिवहन योजना, प्रवर्तन और जागरूकता में अंतराल को उजागर करता है। 2030 तक सड़क पर होने वाली मौतों को आधा करने के एसडीजी लक्ष्य को पूरा करने के लिए, भारत को प्रवर्तन, इंजीनियरिंग, शिक्षा और आपातकालीन देखभाल के संयोजन के लिए एक बहु-आयामी रणनीति की आवश्यकता है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: किस राज्य ने 2023 में दोपहिया दुर्घटनाओं में सबसे अधिक मौतें दर्ज कीं?

- (a) उत्तर प्रदेश
- (b) तमिलनाडु
- (c) महाराष्ट्र
- (d) राजस्थान

उत्तर: (b)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारत में सड़क सुरक्षा न केवल यातायात प्रबंधन का मुद्दा है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और शासन का भी मामला है। NCRB 2023 डेटा के संदर्भ में आलोचनात्मक विश्लेषण करें। (150 शब्द)

किसान आत्महत्याएं भारत में एक गंभीर सामाजिक-आर्थिक मुद्दा बनी हुई हैं, जो ऋण, फसल की विफलता और नीतिगत अंतराल के कारण कृषि क्षेत्र में संकट को दर्शाती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, कुल 10,786 किसानों और कृषि श्रमिकों ने आत्महत्या की, जो देश में कुल आत्महत्याओं का 6.3% है।

Maharashtra, Karnataka report most number of farmer suicides

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The National Crime Records Bureau (NCRB) has said in its report that 10,786 farmers and agricultural workers committed suicide in 2023. The most number of cases was from Maharashtra (38.5%), followed by Karnataka (22.5%).

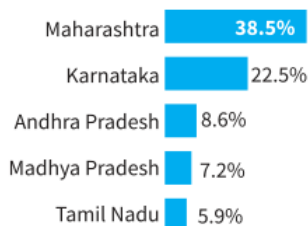
The organisations of farmers blamed the Narendra Modi government's policies for the situation, and said the decision to waive off import duty on cotton would vitiate the situation as most of the suicides were still from the cotton belts of the country.

Of the 10,786 suicides from the farming sector, 4,690 were farmers or cultivators, and 6,096 were agricultural workers. The farm suicides accounted for 6.3% of total suicides

Fields of despair

The lives of 10,786 farmers and agricultural workers were lost to suicide in 2023, according to the NCRB report

STATE-WISE FIGURES



A large number of farmer suicides take place in the cotton and soybean belt in Maharashtra.

(1,71,418 suicides in 2023) in the country.

Out of the 4,690 farmers who committed suicide, 4,553 were male and 137 were female, and out of the 6,096 suicides by farm workers, 5,433 were male and 663 were female.

After Maharashtra and Karnataka, Andhra Pradesh (8.6%), Madhya Pradesh (7.2%), and Tamil Nadu (5.9%) registered the most number of suicides. West Bengal, Bihar, Od-

isha, Jharkhand, Himachal Pradesh, Arunachal Pradesh, Goa, Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura, Chandigarh, Delhi, and Lakshadweep reported no suicides from the farm belt.

Commenting on the NCRB data, the president of the All India Kisan Sabha, Ashok Dhawale, said more than 10,000 suicides had been reported from the farm sector in 2021, 2022 and 2023, and it

showed the systemic crisis that the Modi government could not grasp or combat.

"This crisis is going to aggravate as a large number of farmer suicides take place in the cotton and soybean belt. Maharashtra has turned out to be the graveyard of farmers. The Marathwada and Vidarbha region are cotton and soybean belts. In spite of this, the Union government is bowing to the pressure to sign Free Trade Agreements, and to U.S. President Donald Trump's tariff terrorism. The government cancelled the 11% import duty on cotton. This means that American cotton is going to come here. Agriculture will be finished by these treaties," Mr. Dhawale said, adding that the NCRB data could not be trusted.

For those in distress, counselling is available at TeleMANAS-14416

वर्तमान संदर्भ

राज्यवार वितरण:

- महाराष्ट्र: 38.5% किसानों ने आत्महत्या की; मुख्य रूप से मराठवाड़ा और विदर्भ (कपास और सोयाबीन बेल्ट) में।
- कर्नाटक: 22.5% आत्महत्याएं।
- अन्य उल्लेखनीय राज्य: आंध्र प्रदेश (8.6%), मध्य प्रदेश (7.2%), तमिलनाडु (5.9%)।

- पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप में आत्महत्या की कोई खबर नहीं है।
- **लिंग और श्रेणी:**
 - किसान/किसान: 4,690 (4,553 पुरुष, 137 महिलाएं)
 - कृषि श्रमिक: 6,096 (5,433 पुरुष, 663 महिला)
- **नीतिगत चिंताएं:**
 - किसान संगठन संकट को बढ़ाने के लिए जीएसटी, कपास पर आयात शुल्क छूट और मुक्त व्यापार समझौतों की आलोचना करते हैं।
 - कपास और सोयाबीन बेल्ट विशेष रूप से वैश्विक मूल्य में उतार-चढ़ाव और व्यापार दबावों के प्रति संवेदनशील हैं।
- सहायता के उपाय: संकटग्रस्त किसानों की काउंसलिंग के लिए टेलीमानस हेल्पलाइन (14416) उपलब्ध है।

स्थैतिक संदर्भ

1. **भारत में किसान आत्महत्याएं:**
 - कृषि संकट, ऋण का बोझ, फसल की विफलता और बाजार में उतार-चढ़ाव से जुड़ा हुआ है।
 - एनसीआरबी सालाना आत्महत्या के आंकड़े एकत्र करता है; इसमें किसान, खेतिहर मजदूर और अन्य श्रेणियां शामिल होती हैं।
2. **किसान संकट से ग्रस्त क्षेत्र:**
 - कपास बेल्ट: मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, कर्नाटक के कुछ हिस्से।
 - सोयाबीन बेल्ट: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक।
3. **किसान कल्याण के लिए सरकारी योजनाएं:**
 - पीएम-किसान: किसानों को आय सहायता।
 - चुनिंदा फसलों के लिए एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य)।
 - प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीआई): क्रॉप इंश्योरेंस।
 - कुछ राज्यों में ऋण राहत और ऋण माफी।

प्रभाव

1. **आर्थिक:**
 - किसानों की बढ़ती आत्महत्याएं प्रणालीगत कृषि संकट और अस्थिर ग्रामीण आजीविका का संकेत देती हैं।
 - वैश्विक वस्तुओं की कीमतों (जैसे, कपास आयात) के प्रति संवेदनशीलता घरेलू कृषि को प्रभावित करती है।
2. **सामाजिक:**
 - किसानों के बीच मानसिक स्वास्थ्य संकट और ग्रामीण संकट।
 - लैंगिक असमानता दिखाई दे रही है; महिलाओं की आत्महत्याएं कम हैं लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण हैं।

3. नीति और शासन:

- बाजार सुधारों, मूल्य स्थिरीकरण और फसल विविधीकरण की आवश्यकता है।
- कृषि-बीमा, ग्रामीण ऋण प्रणाली और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श को मजबूत करना।
- घरेलू कृषि पर उनके प्रभाव के लिए मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) की निगरानी का महत्व।

निष्कर्ष

NCRB के आंकड़े भारत में विशेष रूप से कपास और सोयाबीन बेल्ट में जारी कृषि संकट को रेखांकित करते हैं। जबकि सरकारी योजनाएं आंशिक राहत प्रदान करती हैं, स्थायी समाधानों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता के साथ-साथ आय सुरक्षा, मूल्य अस्थिरता और ऋण तक पहुंच को संबोधित करने वाले नीतिगत सुधारों की आवश्यकता होती है। किसानों की आत्महत्याएं एक संरचनात्मक चुनौती हैं और ग्रामीण आजीविका की सुरक्षा के लिए समग्र कृषि सुधारों की तत्काल आवश्यकता को दर्शाती हैं।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: 2023 में भारत में किसान आत्महत्याओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें (NCRB डेटा):

1. महाराष्ट्र में 2023 में सबसे अधिक किसान आत्महत्याएं दर्ज की गईं।
2. 2023 में कुल किसान आत्महत्याओं में से 10% से अधिक आंध्र प्रदेश में हुई।
3. कपास और सोयाबीन बेल्ट उन क्षेत्रों में से हैं जो किसानों की आत्महत्याओं से सबसे अधिक प्रभावित हैं।
4. पश्चिम बंगाल और बिहार में 2023 में एक भी किसान आत्महत्या नहीं हुई।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है?

- a) केवल 1, 2, और 3
- b) केवल 1, 3, और 4
- c) केवल 2, 3, और 4
- d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: वैश्विक व्यापार नीतियों और घरेलू कृषि सुधारों के संदर्भ में भारत में जारी किसान आत्महत्या संकट की गंभीर रूप से जांच करें। सरकार प्रणालीगत कृषि संकट को कैसे संबोधित कर सकती है? (150 शब्द)

महिला श्रम बल भागीदारी दर (एफएलएफपीआर) उन महिलाओं की हिस्सेदारी को मापती है जो कार्यरत हैं या सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रही हैं। एक बढ़ती हुई FLFPR को अक्सर अधिक लैंगिक समानता और आर्थिक गतिशीलता के संकेत के रूप में व्याख्या की जाती है। भारत में, FLFPR 2011-12 में 31.2% से गिरकर 2017-18 में 23.3% हो गया, 2023-24 में तेजी से बढ़कर 41.7% हो गया। पहली नज़र में, यह उत्साहजनक लगता है; हालाँकि, रोजगार के प्रकारों और कमाई की बारीकी से जांच करने से संरचनात्मक कमजोरियों का पता चलता है।

More women join the labour force, but are they really employed?

In rural areas, it is difficult to separate women's domestic responsibilities from their role as helpers in household enterprises

DATA POINT

Subhanil Chowdhury
Anushree Gupta

The female labour force participation rate (FLFPR) measures the share of women who are either employed or actively seeking work. A higher FLFPR is often seen as a sign of greater gender equality and a more dynamic labour market. The FLFPR fell from 31.2% in 2011-12 to 23.3% in 2017-18, before climbing to 41.7% in 2023-24 (Chart 1). While this rise appears encouraging, a closer look reveals that women continue to face barriers – both in terms of earnings and the kind of jobs available to them.

In India, workers are broadly classified into three categories: self-employed, regular salaried, and casual workers. The NSSO tracks earnings for each of these groups. Strikingly, during the very period when the FLFPR rose, real earnings declined for all categories except casual workers in both rural and urban areas. This points to a troubling reality – more women may be entering the workforce, but they are not finding secure or remunerative employment.

Chart 1 shows that the recent rise in FLFPR is largely driven by rural women. To understand this trend better, we now turn to a closer examination of female labour force participation and employment patterns in rural India.

Economic development is typically associated with a shift of the workforce from agriculture to non-agricultural sectors. Given the recent rise in rural FLFPR, one might expect more women to be moving out of agriculture into industry or services. The data, however, suggest the opposite. The share of rural women employed in agriculture rose from 71.1% in 2018-19 to 76.9% in 2023-24, while their presence in both the secondary and tertiary sectors declined (Chart 2).

A large share of women's work takes the form of unpaid household labour, which does not count as employment in official statistics. Even within the employed category, there exists a group termed 'helpers in household enterprises' – a role that also falls under unpaid family work. So, two categories capture women attending to domestic duties, both of which are unpaid activities.

Among rural women aged 15 years and above, there has been a sharp fall in those reporting 'domestic duties' – from 57.8% in 2017-18 to 35.7% in 2023-24 (nearly 20 percentage points). This shift is mirrored by a 10.5 point rise in women counted as 'helpers in household enterprises' (from 9.1% to 19.6%) and a 10 point rise in 'own account workers and employers' (from 4.5% to 14.6%) over the same period (Chart 3). In other words, the reduction in unpaid domestic work has translated largely into self-employment, not into an expansion of wage employment.

In rural areas, it is often difficult – if not impossible – to separate women's domestic responsibilities from their role as helpers in household enterprises. This blurring of boundaries may partly explain the rise in FLFPR. It also raises a fundamental question: should such unpaid helper roles be counted as employment at all? At the same time, even within the self-employed category, the apparent increase in own account workers and employers has coincided with a decline in their real earnings. In other words, the rise in self-employment has not improved women's incomes (Chart 4).

Thus, the rise in FLFPR is largely driven by an increase in women counted as helpers in household enterprises and as self-employed workers. Wage employment has not expanded, and real earnings for most categories of women workers have actually fallen. Far from signalling dynamism, this pattern points to deeper vulnerabilities in the labour market.



Facing barriers

The data for the charts were sourced from the Periodic Labour Force Survey and NSSO

Subhanil Chowdhury is an associate professor of Economics at St. Xavier's University, Kolkata. Anushree Gupta is an MA student in Department of Economics, St. Xavier's University, Kolkata

Chart 1: The female labour force participation rate (for women aged 15 years and above)

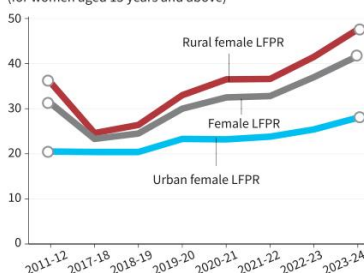


Chart 2: Sectoral distribution of women employment in rural India. Figures in %

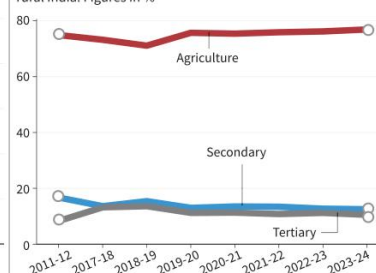


Chart 3: Paid and unpaid work of women in rural India. Figures in %

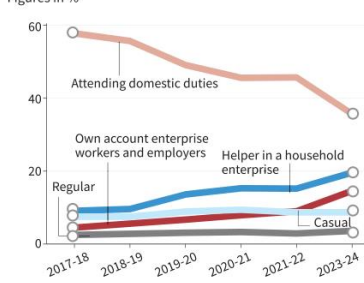
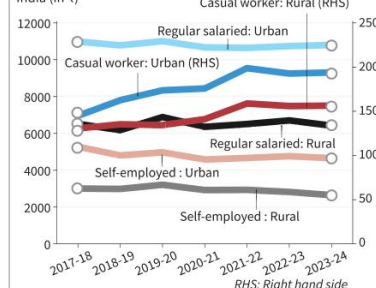


Chart 4: Real wage and earnings of female workers in India (in ₹)



वर्तमान संदर्भ

1. भारत में रोजगार श्रेणियाँ:

- स्व-नियोजित/स्वयं के खाते वाले कर्मचारी और नियोजक

- नियमित वेतनभोगी कर्मचारी
- आकस्मिक कर्मचारी

एफएलएफपीआर में वृद्धि के बावजूद, आकस्मिक श्रमिकों को छोड़कर सभी श्रेणियों के लिए वास्तविक आय में गिरावट आई है, जो असुरक्षित और कम वेतन वाले रोजगार को उजागर करती है।

2. क्षेत्रीय वितरण:

- कृषि में कार्यरत ग्रामीण महिलाएं 71.1% (2018-19) से बढ़कर 76.9% (2023-24) हो गईं।
- द्वितीयक (उद्योग) और तृतीयक (सेवा) क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति में गिरावट आई।

3. अवैतनिक कार्य और घरेलू उद्यम:

- कई महिलाएं अवैतनिक घरेलू श्रम में या घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में लगी हुई हैं, जो आर्थिक सुरक्षा में सुधार किए बिना एफएलएफपीआर को बढ़ाते हैं।
- घरेलू कर्तव्यों की रिपोर्ट करने वाली महिलाओं में गिरावट (57.8% → 35.7%) बड़े पैमाने पर मजदूरी रोजगार के बजाय स्व-रोजगार या अवैतनिक सहायक भूमिकाओं में तब्दील हो गई।

4. आय निहितार्थ:

- स्व-नियोजित महिलाओं के लिए वास्तविक कमाई में गिरावट आई है, जिसका अर्थ है कि एफएलएफपीआर में वृद्धि बेहतर वित्तीय सुरक्षा के अनुरूप नहीं है।

स्थैतिक संदर्भ

- एफएलएफपीआर: 15+ आयु वर्ग की महिलाओं का हिस्सा नौकरीपेशा या सक्रिय रूप से काम की तलाश में।
- भारत में श्रम बल की भागीदारी की प्रवृत्ति: सांस्कृतिक मानदंडों, अवैतनिक घरेलू काम और सीमित औपचारिक रोजगार के अवसरों के कारण महिलाओं के लिए ऐतिहासिक रूप से कम।
- ग्रामीण रोजगार: कृषि और अनौपचारिक स्वरोजगार का प्रभुत्व; महिलाओं के लिए मजदूरी रोजगार सीमित है।

प्रभाव

1. आर्थिक:

- एफएलएफपीआर में वृद्धि बेहतर आय या आर्थिक सशक्तिकरण की गारंटी नहीं देती है।
- अनौपचारिक और अवैतनिक कार्य महिला रोजगार पर हावी है, जो ग्रामीण श्रम बाजारों में भेद्यता को उजागर करता है।

2. सामाजिक:

- घरेलू जिम्मेदारियाँ और लैंगिक कार्य विभाजन जैसी संरचनात्मक बाधाएँ औपचारिक रोजगार में महिलाओं की भागीदारी को सीमित करती रहती हैं।
- अवैतनिक भूमिकाओं के कारण महिलाओं के आर्थिक योगदान को अक्सर कम करके आंका जाता है।

3. नीति और शासन:

- महिलाओं के लिए औपचारिक वेतन रोजगार को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- कौशल विकास कार्यक्रमों को ग्रामीण महिलाओं को लक्षित करना चाहिए ताकि वे द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में संक्रमण को सुगम बना सकें।
- सामाजिक सुरक्षा, मातृत्व लाभ और श्रम कानून सुधार स्वरोजगार और अनौपचारिक क्षेत्रों में महिलाओं की रक्षा कर सकते हैं।

निष्कर्ष

भारत के एफएलएफपीआर में हालिया वृद्धि को महिला सशक्तिकरण के रूप में व्याख्या किए जाने पर भ्रामक है, क्योंकि यह बड़े पैमाने पर अवैतनिक घरेलू काम और घटती कमाई के साथ स्वरोजगार से प्रेरित है। लिंग-समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए, नीतियों को केवल श्रम बल में महिलाओं की गिनती करने के बजाय औपचारिक रोजगार के अवसरों, उचित मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न : महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) क्या है?

- a) 15+ आयु वर्ग की महिलाओं का प्रतिशत नियोजित या सक्रिय रूप से काम की तलाश में
- b) केवल कृषि में कार्यरत 15+ आयु वर्ग की महिलाओं का प्रतिशत
- c) न्यूनतम मजदूरी से अधिक कमाई करने वाली महिलाओं का प्रतिशत
- d) व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकित महिलाओं का प्रतिशत

उत्तर: a)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) में वृद्धि ने महिलाओं के लिए बेहतर कमाई या सुरक्षित रोजगार में अनुवाद नहीं किया है। इस प्रवृत्ति के पीछे के कारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें और ग्रामीण भारत में महिलाओं के सार्थक आर्थिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत उपायों का सुझाव दें। (150 शब्द)

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) भारत के पूंजी बाजारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो बाजार की तरलता, निवेश प्रवाह और मूल्यांकन में योगदान करते हैं। सितंबर 2025 में, एफपीआई ने भारतीय इक्विटी से ₹23,885 करोड़ निकाल लिए, जो निवल आउटफ्लो के लगातार तीसरे महीने को चिह्नित करता है। जनवरी और सितंबर 2025 के बीच, संचयी एफपीआई आउटफ्लो ₹1.54 लाख करोड़ तक था, जो पिछले वर्ष के आउटफ्लो से अधिक था।

वर्तमान संदर्भ

1. FPI निवेश का रुझान:

○ कैलेंडर वर्ष 2025:

- जनवरी: 78,000 करोड़ रुपये का शुद्ध प्रवाह
- फरवरी-मार्च: बहिर्वाह
- अप्रैल-जून: मध्यम प्रवाह
- जुलाई-सितंबर: लगातार बहिर्वाह

- कैलेंडर वर्ष 2024: अक्टूबर में ₹94,000 करोड़ का सबसे अधिक बहिर्वाह; सितंबर 2024 तक शुद्ध प्रवाह ₹1 लाख करोड़ था।

2. बहिर्वाह के कारण:

○ वैश्विक कारक:

- फार्मास्यूटिकल्स पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ाना
- एच-1बी वीजा शुल्क में बढ़ोतरी से धारणा प्रभावित
- वैश्विक उभरते बाजार फंडों में चीन का आवंटन बढ़ रहा है (सितंबर 2024 में 21% से → 2025 में 28.8%)

○ घरेलू कारक:

- कई तिमाहियों के लिए सुस्त कॉर्पोरेट आय
- भारतीय इक्विटी का उच्च मूल्यांकन
- डॉलर रिटर्न को कम करने से रुपये का अवमूल्यन

FPIs withdraw from Indian equities for third straight month

Analysts say the reasons range from tariff uncertainty to dull company earnings for multiple quarters and disproportionately high valuations

Ashokamithran T.
MUMBAI

Foreign Portfolio Investors (FPIs) withdrew ₹23,885 crore from Indian stocks in September, making it the third consecutive month of net outflows from the Indian stock market, according to data from the National Securities Depositories Ltd. (NSDL).

FPIs have been withdrawing money from the Indian stock market since September 2024, on and off. To be sure, the calendar year began with a net flow of more than ₹78,000 crore in January 2025 after which there were two consecutive months of outflows. This was followed by moderate inflows in April, May and June 2025.

Sentiments were pessimistic even in calendar year 2024, with the highest ever outflows in October going as high as ₹94,000 crore.

Despite this, FPIs had a net inflow of ₹1 lakh crore as of September 2024.

However, between January and September this year, foreign investors have pulled out ₹1.54 lakh crore from Indian equities, making it worse than the previous year.

Some analysts cite short-term reasons like the uncertainty in tariffs, while others say that dull earnings



Losing sheen: Between January and Sept. 2025, foreign investors have pulled out ₹1.54 lakh crore from Indian equities. PTI

of companies for multiple quarters and disproportionately high valuations have made these stocks unattractive. The increasing rupee depreciation makes the dollar returns smaller.

According to a report by Elara Capital, managers of emerging market funds have cut India allocation to 16.7%, which is the worst since November 2023.

India constituted 21% of their allocation in September 2024. These funds are instead moving to China.

"Active global emerging market (GEM) managers remain net sellers of India [stocks], continuing to rotate towards China. India's allocation in GEM funds peaked at 21% in September 24 but has since fallen sharply to 16.7% [lowest since November 23]. In contrast, China's allocation has climbed to 28.8%, marking a decisive reversal in positioning," according

to Elara's report.

"As of August 2025, global funds held \$390 billion in Indian assets. Of these, funds with high conviction in India's long-term growth have been withdrawing from the country. This is the first such instance since April 2018 and "raises questions about the strength and sustainability of foreign investor conviction in India's medium-term growth story," says another report by Elara.

Domestic markets

Returns in domestic markets have also been dull. For instance, Nifty50 index was down 4.6% to 24,611.1 points on September 1, 2025, from 25,810.85 on the same day last year.

Analysts say that FPI flows will continue to be volatile given the H1-B visa fee hike, the 100% U.S. tariff on branded pharmaceuticals, and a ramp up in Chinese investments in AI.

3. घरेलू बाजारों पर प्रभाव:

- निफ्टी50 ने सितंबर 2025 में 4.6% YoY से 24,611 पॉइंट तक अस्वीकार कर दिया।
- एफपीआई प्रवाह में उतार-चढ़ाव बाजार के विश्वास और पूंजी की उपलब्धता को प्रभावित करता है।

स्थैतिक संदर्भ

1. विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI):

- प्रत्यक्ष प्रबंधन नियंत्रण के बिना भारतीय शेयरों और बॉन्डों में विदेशी निवेशकों द्वारा किया गया निवेश।
- एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) के विपरीत, जिसमें स्वामित्व और नियंत्रण शामिल है।

2. एफपीआई का महत्व:

- इक्विटी बाजारों को तरलता और गहराई प्रदान करता है।
- शेयर बाजार के मूल्यांकन को प्रभावित करता है।
- यह भारत की वृहद आर्थिक स्थिरता में विदेशी निवेशकों के विश्वास के संकेत के रूप में कार्य करता है।

3. इमर्जिंग मार्केट फंड (GEM फंड):

- विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की इक्विटी में निवेश करने वाले फंडों का सक्रिय रूप से प्रबंधन किया।
- भारत, चीन आदि के बीच आवंटन में बदलाव पूंजी प्रवाह और बाजार की धारणा को प्रभावित करते हैं।

प्रभाव

1. आर्थिक और वित्तीय:

- बड़े एफपीआई आउटफ्लो से बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है और इक्विटी फाइनेंसिंग प्रभावित हो सकती है।
- कमजोर एफपीआई सेंटिमेंट से विदेशी मुद्रा भंडार और रुपये पर असर पड़ सकता है।
- घरेलू निवेशकों को पूंजी प्रवाह में कमी की भरपाई करने की आवश्यकता हो सकती है।

2. नीति और शासन:

- आरबीआई और सेबी के उपायों के माध्यम से पूंजी प्रवाह स्थिरता की निगरानी करने की आवश्यकता है।
- दीर्घकालिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए संरचनात्मक सुधारों के महत्व पर प्रकाश डालें।
- टैरिफ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और निवेश के माहौल को प्रभावित करने वाली नीतियां एफपीआई प्रवाह को बदल सकती हैं।

3. वैश्विक संदर्भ:

- भारत से चीन तक वैश्विक फंड रोटेशन भू-राजनीतिक और आर्थिक बदलावों को दर्शाता है।
- प्रौद्योगिकी (एआई) और व्यापार नीतियों में अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा उभरते बाजार आवंटन को प्रभावित करती है।

निष्कर्ष

एफपीआई की निकासी का लगातार तीसरा महीना भारत के शेयर बाजारों को लेकर विदेशी निवेशकों के बीच सतर्कता का संकेत देता है। जबकि भारत एक आकर्षक उभरता हुआ बाजार बना हुआ है, उच्च मूल्यांकन, सुस्त आय, मुद्रा मूल्यहास और वैश्विक व्यापार तनाव जैसी चुनौतियां अस्थिरता में योगदान करती हैं। विश्वास बहाल करने और दीर्घकालिक निवेश स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन, व्यापार नीति और बाजार पारदर्शिता में निरंतर सुधार आवश्यक हैं।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

- a) FPI में कंपनियों का प्रत्यक्ष प्रबंधन नियंत्रण शामिल है
- b) FPI स्टॉक मार्केट को लिक्विडिटी प्रदान करते हैं
- c) FDI अल्पकालिक पोर्टफोलियो निवेश को संदर्भित करता है
- d) FPI वैश्विक फंड आवंटन रुझानों से प्रभावित नहीं होते हैं

उत्तर : b)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारत के पूंजी बाजारों में एफपीआई की भूमिका की गंभीर जांच करें। क्या भारत को सतत आर्थिक विकास के लिए एफपीआई की तुलना में एफडीआई पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए? **(150 शब्द)**

The transformation of girls' education

In a country where the phrase “*Beti padhegi toh kya karegi?* (What will a daughter do if she studies?)” once echoed through homes and villages, India has undergone a powerful transformation in girls' education over the past decade.

At a *Mahila Sammelan* (Women's Conference) in Dwarka, Gujarat, Prime Minister Narendra Modi asked a group of women how many had studied beyond class 5. To his surprise, most of the elderly women raised their hands, while few younger women did. When asked why, they pointed to the era of the Gaekwad dynasty (1721-1947), when fathers were penalised for not educating their daughters. Today, however, many women are literate, while their daughters-in-law are not.

This anecdote underscores a larger truth: good intentions must be backed by accountability, leadership, and policy. And under Mr. Modi's leadership, India is witnessing just that – a systemic push to change not just rules, but mindsets. This transformation is not just about more girls in classrooms; it's about shifting the very foundations of Indian society, its health, economy, and demography, by empowering its daughters with the most effective tool of change: education.

The Gujarat model

As Chief Minister of Gujarat, Mr. Modi recognised that tackling issues such as female foeticide and girls' illiteracy required a multi-pronged approach. Laws alone wouldn't suffice; a fundamental shift in public perception, supported by infrastructure and incentives, was required. Launched in 2003, the Kanya Kelavani campaign became a key vehicle for this change. The initiative promoted awareness about girls' education while addressing barriers such as the lack of separate toilets for girls in schools, a major cause of dropouts during adolescence.

The results were significant. Female literacy rate in Gujarat



Shamika Ravi

Member of the Economic Advisory Council to the Prime Minister, and Secretary to Government of India. Views are personal

which was lower than the national average, increased to 70%, higher than the national average of 64%. The school dropout rate reduced by as much as 90% among female students in targeted districts.

Mr. Modi transformed the policy initiative through widespread public support, by personally auctioning gifts received at public events, raising ₹19 crore for girls' education. He also made a personal contribution of ₹21 lakh. These efforts sent a strong signal: girls' education wasn't just a government scheme, it was a public movement.

Scaling success nationwide

Inspired by Gujarat's success, the Beti Bachao, Beti Padhao (BBBP) initiative was launched nationwide in 2015. Its aim was twofold: to prevent female foeticide and promote girls' education. The initiative focused on 100 gender-critical districts in its initial phase and later expanded nationwide. It brought together multiple ministries – Women and Child Development, Health and Family Welfare, and Human Resource Development – in a coordinated push for change. Among other measures of outcome, its impact is most visible in the survival rate of girls. India's sex ratio at birth improved from 919 girls per 1,000 boys (2015-16) to 929 (2019-21). Encouragingly, 20 out of 30 States/UTs are performing better than the national average of 930.

But these improvements in sex ratio at birth are encouraging, they are just one piece of a much larger puzzle. The real power of girls' education lies in the ripple effects it triggers across society. Educated women tend to marry later and have fewer children. India's Total Fertility Rate has dropped to 2.0, just below replacement level. This shift is closely tied to rising female education and workforce participation. Women with secondary education are more likely to seek institutional deliveries and prenatal care. The

Infant Mortality Rate for girls has dropped from 49 per 1,000 live births in 2014 to 33 by 2020. While overall female labour force participation remains a challenge, it is rising in sectors such as healthcare, education, STEM, and entrepreneurship – fields that thrive on literacy and skills. From officers in the armed forces to CEOs of tech startups, today's educated Indian women are breaking barriers.

The multiplier effect

Educated girls grow into educated mothers – and that changes everything. Studies show that children of educated mothers perform better in school and experience better health outcomes. In Madhya Pradesh, recent surveys show that 89.5% of people are aware of BBBP, and 63.2% say it directly encouraged them to send their daughters to school. Communities reported increased support for delaying early marriage and promoting girls' higher education. These statistics reflect changing mindsets in regions where girls were once kept from schools entirely.

This transformation is a deep-rooted change facilitated by thoughtful and effective policies aimed at empowering young women. The long-term impact of these initiatives will be even more pronounced because of the positive feedback cycle that enhances not only individual lives but entire communities. Today's educated girls are not merely students; they are potential leaders, advocates, and change-makers of tomorrow. Educated girls are more likely to join the workforce, contribute to their families' incomes, and invest in the education of their children.

As we look to the future, we can be hopeful that the changes initiated under Mr. Modi's leadership will continue to gain momentum, leading to a more equitable society where every girl has the right to learn, grow, and thrive. Let's be clear: when you educate a girl, you save a society.

The Beti Bachao, Beti Padhao initiative has shown significant results in the last decade

GS. Paper 01 & 02- सामाजिक मुद्दे और शासन

UPSC Mains Practice Question: भारत में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने में बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोणों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। (150 शब्द)

संदर्भ:

भारत में लड़कियों की शिक्षा में पिछले दो दशकों में एक नाटकीय परिवर्तन देखा गया है, जो हाशिए और सामाजिक उपेक्षा से एक संरचित, नीति-संचालित फोकस की ओर बढ़ रहा है। एक बार इस कहावत से सवाल किया गया था, "बेटी पढ़ेगा तो क्या करेगी?" देश ने साक्षरता, अस्तित्व और शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी में पर्याप्त प्रगति की है, जो व्यापक सामाजिक और जनसांख्यिकीय परिवर्तन का संकेत है।

वर्तमान संदर्भ

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- पारंपरिक सामाजिक मानदंडों ने लड़कियों की शिक्षा को सीमित कर दिया, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
- 20वीं सदी के शुरुआती सुधारों (उदाहरण के लिए, गायकवाड़ राजवंश के तहत) ने महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया, जिससे बाद की प्रगति के लिए आधार तैयार किया गया।

2. गुजरात मॉडल - कन्या केलावानी (2003 के बाद):

- लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों सहित जागरूकता, प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचे के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या और लड़कियों की निरक्षरता से निपटा गया।
- परिणाम:
 - गुजरात में महिला साक्षरता बढ़कर 70% हो गई, जो राष्ट्रीय औसत (64%) से अधिक है।
 - लक्षित जिलों में लड़कियों के बीच स्कूल छोड़ने की दर में 90% तक की गिरावट आई है।
- सार्वजनिक भागीदारी: पीएम मोदी ने व्यक्तिगत रूप से उपहारों की नीलामी की और धन का योगदान किया, जिससे लड़कियों की शिक्षा के लिए एक जन आंदोलन पैदा हुआ।

3. राष्ट्रीय स्केलिंग - बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP, 2015):

- लक्ष्य: कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना।
- लक्षित लिंग-संवेदनशील जिले, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालयों में समन्वित।
- परिणाम:
 - जन्म के समय लिंगानुपात 919 लड़कियों/1,000 लड़कों (2015-16) से बढ़कर 929 (2019-21) हो गया।
 - जागरूकता अभियानों ने समुदायों को कम उम्र में शादी में देरी करने और लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए प्रभावित किया।

4. लड़कियों की शिक्षा के प्रभाव

- जनसांख्यिकीय प्रभाव: कुल प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर के करीब 2.0 तक गिर गई।
- स्वास्थ्य परिणाम: लड़कियों के लिए शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) 49 (2014) से गिरकर 33 (2020) हो गई।
- आर्थिक भागीदारी: स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, एसटीईएम और उद्यमिता में महिला कार्यबल की बढ़ती भागीदारी।

स्थैतिक संदर्भ

1. प्रमुख योजनाएँ और पहल:

- कन्या केलावानी (गुजरात) – राज्य स्तरीय शिक्षा को बढ़ावा देना।
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP) - लैंगिक समानता और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पहल।

2. संकेतक:

- महिला साक्षरता दर, स्कूल छोड़ने की दर, जन्म के समय लिंग अनुपात, कुल प्रजनन दर, महिला श्रम बल भागीदारी।

3. सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:

- शिक्षित लड़कियाँ शिक्षित माँ बन जाती हैं, जिससे बाल स्वास्थ्य, शिक्षा और घरेलू आर्थिक परिणामों में सुधार होता है।
- शिक्षा लड़कियों को नेतृत्व, उद्यमिता और शासन में बाधाओं को तोड़ने का अधिकार देती है।

प्रभाव**1. सामाजिक:**

- लैंगिक भूमिकाओं और महिला सशक्तिकरण के बारे में मानसिकता में बदलाव।
- बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं में कमी।

2. आर्थिक:

- उच्च महिला साक्षरता और कार्यबल भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि में योगदान करती है।
- शिक्षित महिलाएँ बच्चों की शिक्षा में अधिक निवेश करती हैं, जिससे मानव पूंजी विकास का एक अच्छा चक्र बनता है।

3. जनसांख्यिकी:

- देर से विवाह और कम बच्चे प्रजनन दर को कम करते हैं, जिससे जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार होता है।
- बेहतर मातृ शिक्षा बाल स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में सुधार करती है।

4. नीति एवं शासन:

- जागरूकता, बुनियादी ढाँचे और प्रोत्साहनों को मिलाकर बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण प्रभावी हैं।
- जन भागीदारी कार्यक्रमों की जवाबदेही और स्थिरता को मजबूत करती है।

निष्कर्ष

लड़कियों की शिक्षा में भारत का परिवर्तन एक बहुआयामी उपलब्धि है। साक्षरता से लेकर स्वास्थ्य, कार्यबल की भागीदारी और सामाजिक सशक्तिकरण तक, सकारात्मक प्रभाव गहरे हैं। कन्या केलावानी और बीपी जैसे कार्यक्रम प्रदर्शित करते हैं कि नीति, नेतृत्व और सामुदायिक जुड़ाव एक साथ प्रणालीगत परिवर्तन लाते हैं। लड़कियों को शिक्षित करना न केवल व्यक्तियों का उत्थान करता है बल्कि पूरे समुदायों और समाज को बदल देता है, इस विचार को पुष्ट करता है कि "जब आप एक लड़की को शिक्षित करते हैं, तो आप एक समाज को बचाते हैं।"